ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Request for Loans to Co-operative Spinning Mills

*201. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Maharashtra has requested Central financial institutions to sanction long term loans expeditiously to the Cooperative Spinning Mills in Maharashtra which are proposed to be set-up in the State:

(b) if so, the details thereof; and

(c) What decision has been taken so far in the matter?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी० बी० आई०) को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में 50 सहकारी कताई मिलों की स्थापना के उसके इरादे की सूचना मिली है । तथापी, आई० डी० बी० आई० को अभी तक वित्तीय सहायता के बारे में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महोदय, यह केवल आई० डी० बी० आई० को कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इतना मर्यादित नहीं है। महाराष्ट्र सरकार भारत सरकार से गये 10 साल से यह प्रोपोजल लेकर आती है। इतना ही नहीं नेशनल फोरम पर भी इसका जिक्र किया गया, एन० डी० सी० और प्लानिंग के फोरम पर भी कि ये जो किसान हैं ये जो कपास उगाते हैं उनके लिए कोआपरेटिव सेक्टर में मिलें बनायी गयी है। तो इसके लिए एक विशेष प्रावधान बनाना भी सरकार ने तय किया था। लेकिन आज एक ऐसा स्टेप हो गया है कि कहीं कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मशीनरी आ जाती है तब भी सरकार उसको कोई मदद नहीं करती है। इसकी वजह से हमारा जो किसान है वह डूब रहा है। इसलिए भारत सरकार का यह प्रथम कर्तव्य होगा क्योंकि यह तो सब पैसा वापस आने वाला है कोई डूबने वाला नहीं है। तो उनको जल्द से जल्द सुविधा प्राप्त करा देना यह दोनों सरकारों का काम है। महाराष्ट्र सरकार तो इक्विटी एक को नौ दे रही है और पांच दे रही है। तो भारत सरकार द्वारा यह डाइरेक्शन बैंकों के लिए देना जरूरी है। यह कितने दिन में तय करोगे। कुछ उसका फारमूला तो तय करोगे कि नहीं ?

डा० अबरार अहमद: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन आई० डी० बी० आई० जो ऋण देती है उसके लिए ऋण प्राप्त करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। अभी मात्र राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि वह 50 नयी कताई मिलें कोआपरटिव सेक्टर में लगाना चहती है। लेकिन वह कहां लगाएगी, उसका क्या डेट होगा, उसका क्या इक्विटी रेशियो होगा, उसके लिए प्रापर आवेदन और एप्लीकेशन दी जाती है जिसके अंदर निश्चित मर्यादाओं की जांच होती है उसके बाद ही कोई ऋण दिया जाता है। तो माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं लेकिन जब तक वह आवेदन नहीं दिया जाता है और उसके अंदर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं होतीं, ऋण देना संभव नहीं होगा।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं यह बताना चाहता हूं कि एक बार नहीं कई बार यह आवेदन दे दिया है भारत सरकार को ... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: The problem is that these applications have not been sent. Why don't you ask the Maharashtra Government to send the applications.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: No, Sir. This matter has already been taken up with the Ministry of Textiles and reminders have been sent a number of times. I will give full particulars to the hon. Minister. If you want, I can place it on the Table of the House.

दस साल से भी ज्यादा है।

I was...

MR. CHAIRMAN: Please ask your second supplementary.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक्सपोर्ट ओरियंटेड कई मिलों की परवानगी दे दी गयी है, क्या सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि एक्सपोर्ट ओरियंटेड महाराष्ट्र की मिलें काफी मुनाफा कर रही हैं? अभी मिलों का आधा काम पूर्ण हो गया है जहां मशीनरी भी लगी है और जिनको परमिशन भी मिली है। दो मिलें एक्सपोर्ट ओरियंटेड हैं। एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए है। वह भी अच्छा काम कर रही है – एक्सपोर्ट ओरियंटेड। दूसरी एक सांगोला में है, वह अच्छी तरह से काम कर रही है। मैं शोलापुर जिले का ही उदाहरण दे रहा हूं जहां से मैं आता हूं। अभी दो मिलें और एक्सपोर्ट ओरियंटेड आ रही हैं जो कोआपरेटिव सेक्टर से लोन ले रही हैं जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। आपको ज्यादा फारेन एक्सचेंज मिल रहा है। ऐसी मिलें सेपरेट करके उनके लिए आप लोने देने के लिए इमीडियेटली डाइरेक्शन दें।

डा० अबरार अहमद: सभापति महोदय किसी एक व्यक्तिगत इकाई के बारे में तो मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं। लेकिन हां अभी तक कुल 35 इकाइयां ऐसी है जो महाराष्ट्र .... (**व्यवधान**)

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं व्यक्तिगत के बारे में नहीं कह रहा हूं। एक्सपोर्ट ओरियंटेड मिलों के बारे में है। व्यक्तिगत को मत दीजिए। व्यक्तिगत को एक पैसा मत दीजिए।

डा० अबरार अहमद: सभापति महोदय, जो कोआपरेटिव सेक्टर की अभी टोटल 35 मिलें महाराष्ट्र के अंदर हैं और उसके अंदर 26 मिलें ग्रोअर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिलें हैं तथा 9 वीवर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिलें हैं। उनमें से अभी 50 परसेंट से ज्यादा जो मिलें कार्य कर रही हैं उन पर ओवरड्यू है। तो हमने राज्य सरकार को यह सलाह दी है कि जो भी नयी मिलें वे स्थापित करना चाहते हैं उसमें पहले जो पुरानी मिलें हैं उनका जो ओवरड्यू है उसको वे क्लियर करें। वैसे राज्य सरकार ने इस संदर्भ में एक मीटिंग – अ ई० एफ० सी० अ ई० ने हमें यह सूचित किया है कि एक मीटिंग अभी जून के महीने में की थी जिसमें 240 करोड़ रुपया उन्होंने नयी लगने वाली मिलों के लिए निर्धारित किया है। उसका डेट इक्विटी रेशियो भी 1 : 1 रखने के बारे में तथा इसके साथ ही साथ हर सात जो नयी मिलें लगेंगी उनको करीब 90 करोड़ रुपया पर इयर टर्म लोन की आवश्यकता पड़ेगी। यह बात उस मीटिंग के अंदर तय हुई है।

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Sir, I have asked a specific question for the export oriented mills which have done half the job. They have done the construction, they have placed orders for the machinery. I would like to know whether cases of such mills which have been facing problems in getting loan

from any other institution than a particular institution, will be considered by the Government.

डा० अबरार अहमद : सर, माननीय सदस्य के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड . . (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Will you consider it or not? You answer that point.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: I think, the hon. Finance Minister knows better because he has earned more foreign exchange and he will be able to reply.

डा० अबरार अहमद : सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिल्स के बारे में Definitely we will consider और जो सूचना मैंने माननीय सदस्य को दी है, अगर वह इसके अलावा . . . . (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That answers the question.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member was a Finance Minister in Maharashtra. He knows better. You please consider only those applications which are pending with you. Will you clear those applications which are pending with you immediately?

डा० अबरार अहमद : सभापति महोदय, कोआपरेटिव सेक्टर के अंदर जो राज्य सरकार ने मिलें खोलने के बारे में बात कही है, उसके बारे में तो मैंने निश्चित उत्तर दिया है कि अभी कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है और इसके अलावा क्या कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, यह सूचना मेरे पास अभी नहीं है, यह मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, Pandit Jawaharlal Nehru had always clearly emphasised that we should have a very strong cooperative sector in this country. But unfortunately, I have that kind of a feeling created in my mind that we are neglecting the cooperative sector. That is my impression because we are not helping the cooperative sector. We want to establish one National Cooperative Bank and a proposal is there. But nothing has been done so far. Sir, our Finance Minister wants that we should go in for production of Value Added goods instead of having these spinning mills, we are exporting cotton. Sir, the apex bank is prepared to give some advances. The IDBI also should give finances for the spinning sector. In Maharashtra, this is a very big problem. We have cotton but we have no spinning mills to that extent. I would like to know from the Government whether we are going to encourage the cooperative sector and whether we are going to give all assistance to the cooperative sector or not.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Sir, I would like to dispel any impression that our Government is underplaying the importance of the cooperative sector in the process of national development. The real issue is the viability of the projects. If the projects are viable, every possible help will be given to the cooperative sector. In Maharashtra, there are problems with regard to the financing of cooperative mills because in a number of mills, there are overdues and these overdues have to be cleared. Also, I would like to say that as far as export oriented mills are concerned, the existing policy of the IDBI lays adequate emphasis on that and, therefore, if a mill is viable and if, in addition, it is export oriented, there should be no difficulty. The hon. Member referred to the proposal for an Apex Cooperative Bank. I have already written to the hon. Minister for Agriculture expressing our willingness to agree to the setting-up of such a bank under specified conditions. The ball is in the court of the cooperative movement. It is not with the Finance Ministry or the Reserve Bank.

SHRI JAGESH DESAI: Thank you very much, Sir.

***202. [The Questioner (Shri Ram Naresh Yadav) was absent. For answer vide col. . . . . infra]**

***203. [The Questioner (Miss. Saroj Khaparde) was absent. For answer vide col. . . . . infra]**

***204. [The Questioner (Shrimati Kamla Sinha) was absent. For answer *vide* col. . . . . infra.]**